

रजिस्ट्री सं० डी-222



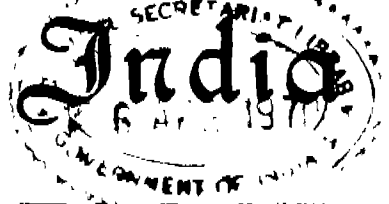
(B)

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 13]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 1970 (चैत्र 7, 1892)

No. 13]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 1970 (CHAITRA 7, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 10 फरवरी 1970 तक प्रकाशित किये गये हैं :

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 10th February 1970:—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
--------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------

—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।
मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिए।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

भाग I—खंड 1—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 315	भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	पृष्ठ 1393
भाग I—खंड 2—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	375	भाग II—खंड 4—रक्षा मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	139
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	21	भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ शोक-मेवा आयोग, रेल प्रणामन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के मेलन तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	349
भाग I—खंड 4—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	377	भाग III—खंड 2—एकत्र कार्यालय कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिमें	121
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं..	69
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश विज्ञापन और नोटिमें शामिल हैं	203
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	941	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिमें	51
		पूरक संख्या 13—	
		21 मार्च 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्टें 27 फरवरी 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	505 517
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	315	PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	PAGE 1393
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	375	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	139
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	21	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	349
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	377	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	121
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	69
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	203
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules, (including Orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	941	PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	51
		SUPPLEMENT No. 13—	
		Weekly Epidemiological Reports for week-ending 21st March 1970	505
		Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 27th February 1970	517

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

मन्त्रिमंडल सचिवालय

(सांख्यिकी विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली-1, दिनांक 5 मार्च 1970

सं० डी० एस०/एस० टी० एस०/4-69—राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण इस समय सांख्यिकी विभाग द्वारा ले लिया गया (उपक्रान्त) है। पश्चिम बंगाल तथा बम्बई नगर को छोड़ कर इसका क्षेत्र-कार्य राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय द्वारा किया जाता है जो एक सरकारी संगठन है, सर्वेक्षण का रूपांकन, आंकड़ों का विधायन, प्रतिवेदनों को तैयार करने का कार्य, पश्चिम बंगाल तथा बम्बई नगर के सम्बन्ध में क्षेत्र-कार्य जैसे समस्त कार्य अधिकरण (एजेन्सी) आधार पर भारतीय सांख्यिकी संस्थान को सौंपे गए हैं। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा इस कार्य पर किए गए व्यय की अनुदान के रूप में सरकार द्वारा पूर्णरूपेण प्रतिपूर्ति की जाती है।

2. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के कार्य पर इस द्वैध (दोहरे) नियन्त्रण के कारण अनेक त्रुटियाँ (न्यूनताएं-कमियाँ) आ गई हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कमी आंकड़ों के संग्रह तथा उनके परिणामों के प्रकाशन के बीच असाधारण विलम्ब है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से सरकार इस बात की जांच करती रही है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के कार्य को किस प्रकार पुनर्गठित किया जाए। सरकार द्वारा 1966 में गठित भारतीय सांख्यिकीय संस्थान विषयक समीक्षा समिति से सिफारिश की कि (पश्चिम बंगाल तथा बम्बई नगर से सम्बन्धित कार्य को छोड़कर) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्य के समस्त पहलुओं को एक ही संगठन को सौंपा जाए। इसके उपरान्त गठित अन्य अनीपचारिक कार्यकारी दलों द्वारा भी इस समस्या की समीक्षा की जा चुकी है।

3. श्री वी० शिवरमन, मन्त्रिमंडल सचिव, प्रोफेसर वी० एम० दंडेकर तथा प्रोफेसर रघुराज बहादुर के योग से गठित त्रिसदस्यीय समिति से हाल में ही अनुरोध किया गया था कि वे सरकार को सलाह दें कि किस प्रकार इस पुनर्गठन को कार्यान्वित किया जाए अन्य बातों के साथ-साथ उक्त समिति ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के कार्य के समस्त पहलुओं को किसी एक ही सरकारी संगठन को सौंपा जाए जो मन्त्रिमंडल सचिवालय में स्थित हो और एक प्रबन्ध (नियन्त्रणकारी) परिषद द्वारा उसका नियमन हो। आगे यह भी सिफारिश की गई कि प्रबन्ध परिषद को निर्णय करने की पर्याप्त स्वतन्त्रता एवं स्वायत्तता (स्वायत्तशामी अधिकार) प्रदान

किए जाएं जिसमें यह सुनिश्चित हो सके कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के संग्रह, विधायन तथा प्रकाशन में किसी प्रकार का अनुचित दबाव न पड़े।

4. सरकार ने त्रि-सदस्यीय (तीन सदस्यों वाली) समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और सांख्यिकी विभाग, मन्त्रिमंडल सचिवालय में "राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन" नामक एक संगठन गठित करने का निर्णय किया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय इस संगठन का एक अंग बन जाएगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के कार्य में लगे हुए भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के समस्त कर्मचारी तथा उभय-निष्ठ सेवाओं में लगे हुए इस प्रकार के कर्मचारी जो संस्थान की आवश्यकता से अधिक हैं, इस संगठन में खपा दिए जाएंगे। इन कर्मचारियों का अन्तर्लयन (सर्विलयन) इस प्रकार की शर्तों पर होगा जिससे उनकी सेवा की दशा में प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

5. सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के समस्त कार्य इस संगठन को सौंपे जाएंगे। इस संगठन के कार्यकलाप का नियमन प्रबन्ध समिति द्वारा होगा जिसका गठन निम्नलिखित है :—

गैर सरकारी व्यक्ति

1. अध्यक्ष
2. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के दो सांख्यिक (संख्या-शास्त्री)
3. विषयविशालयों, अनुसन्धान संस्थानों तथा अन्य निजी संगठनों से दो अर्थशास्त्री

सरकारी व्यक्ति

4. निदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन;
5. राज्य सांख्यिकीय कार्यालयों (ब्यूरो) के दो निदेशक (बारी बारी)
6. केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों/विभागों के दो सांख्यिकीय/आर्थिक सलाहकार (बारी-बारी से)।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के कर्मचारी

7. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के कार्यत्मक प्रभागों के निदेशक, जिनमें, सर्वेक्षण अभिकल्प (डिजाइन) एवं अनुसन्धान आर्थिक विश्लेषण क्षेत्र-संकार्य और अर्कड़ा-विधायन प्रभाग सम्मिलित हैं।

8. मुख्य कार्य-निष्पादन अधिकारी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन—सदस्य-सचिव।

6. अध्यक्ष की नियुक्ति पांच वर्ष के लिए होगी। अन्य गैर सरकारी व्यक्तियों में से प्रत्येक की नियुक्ति की अवधि दो वर्ष की होगी। राज्य सांख्यिकीय कार्यालयों के निदेशक तथा केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों/विभागों के सांख्यिकीय/आर्थिक सलाहकार जो उपर्युक्त परिषद के सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति की अवधि भी दो वर्ष की होगी।

7. प्रबन्ध परिषद को निर्णय करने की अपेक्षित स्वतन्त्रता एवं स्वायत्तता होगी जिससे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के संकलन, विधायन तथा प्रकाशन को अनुचित प्रभाव से मुक्त रखा जा सके। इसे अपने अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कार्यक्रम तैयार करने तथा सरकार द्वारा दिए गए धन की सीमा के भीतर प्रतिवर्ष संगठन का बजट अनुमोदित करने का पूर्ण अधिकार है। इसमें गवेषणा के किसी निश्चित क्षेत्र में या किसी निर्धारित अवधि में विषयों अथवा मदों का चयन जिनके बारे में आंकड़ों का संकलन होना है जिसे वारंवारता के साथ किसी मद के आंकड़े एकत्र करने हैं, विभिन्न पदों के अनुसन्धान एवं विधायन में सापेक्षिक संसाधनों का प्रविस्तार, विभिन्न विषयों पर किए गए सञ्जात्मक अथवा अग्रगामी कार्य, अपनाया जाने वाला प्रतिद्वंद्व अभिकल्प, तैयार किए जाने वाला सारणीकरण, किस रूप में आंकड़ों का संकलन, विधान विश्लेषण तथा परिणामों का प्रकाशन होना है आदि बातें सम्मिलित हैं।

8. प्रबन्ध परिषद को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सांख्यिकीय अभिकरणों के वैध कार्यकलाप का अधिक्रमण नहीं करना चाहिए, भले ही वह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा आंकड़ों के अनुपूरक संग्रह के सहारे अन्य अभिकरणों द्वारा संगृहीत वर्तमान आंकड़ों में सुधार तथा नीतिनिर्धारण के लिए सरकार द्वारा अपेक्षित जानकारी की दृष्टियों को दूर करने के लिए उचित मामलों में कार्य-वाही कर सकती है। ऐसे मामले में सम्बद्ध मन्त्रालयों या अभिकरणों की ओर से पहले (उपक्रमण) हो तो अच्छा है। और जहां इस प्रकार का उपक्रमण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा होता है तो उसे सम्बद्ध मन्त्रालयों अभिकरणों की सहमति और सहायता मिलनी चाहिए। अन्य मन्त्रालयों या अभिकरणों के लिए आंकड़ों के संग्रह एवं सारणीकरण सम्बन्धी अनुरोध सरकार की पूर्व अनुमति के बिना परिषद को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों संग्रहकार्यक्रम को स्थायी एवं सुसंगत बनाने पर जोर देना चाहिए जिससे आंकड़ों की कमियां दूर की जा सकें जो नीतिनिर्धारण तथा कार्यान्वयन की दृष्टि से आवश्यक है वजाए इसके कि एक अभिकरण स्थापित किया जाए जो कई दिशाओं (विभागों) से आने वाले आंकड़ों की तदर्थ मांग को पूरा कर सके।

9. प्रबन्ध समिति को चाहिए कि किसी निश्चित अवधि में पूरा होने वाले सर्वेक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय इस बात का भी संकेत करे कि किस रूप में सर्वेक्षण होना चाहिए और उसका परिणाम कब तक प्रकाशित हो जाना चाहिए। लक्ष्य तो यह होना चाहिए कि परिणामों को सारणियों के रूप में प्रकाशित किया जाए, उसके साथ टिप्पणियां भी होनी चाहिए और सर्वेक्षण पूरा होने के

12 महीने के भीतर ही वह प्रकाशित भी होना चाहिए। सारणियों तथा टिप्पणियों के प्रकाशन के अतिरिक्त आंकड़ों के संग्रह तथा उनके प्रकाशन में विस्तृत आर्थिक विश्लेषण को यह परिषद अपने कार्य का अभिन्न अंग समझे।

10. प्रबन्ध परिषद को सरकार द्वारा दी गई धन राशि की सीमा के भीतर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आय-व्यय (बजट) के अनुमोदन का अधिकार होगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के मुख्य कार्य-निष्पादन अधिकारी जो सांख्यिकी विभाग, मन्त्रिमंडल सचिवालय में पब्लिक सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव भी रहेंगे, वे परिषद द्वारा अनुमोदित बजट तथा उसके द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के ढांचे के अन्दर ही कार्य करेगी और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की कार्यविधि (प्रबन्ध) के लिए उनमें निहित वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों को कार्यान्वित करने के लिए वे उत्तरदायी होंगे। मुख्य कार्य-निष्पादन अधिकारी परिषद के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए औपचारिक आदेश जारी करेंगे।

11. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तथा उसकी परिषद से सम्बद्ध मुख्यधारा 39 में विकलनीय होगा और मांग संख्या 48-सांख्यिकी विभाग से अन्तर्गत लेखांकित होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प (प्रस्ताव) की एक-एक प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाए:—

1. वित्त मन्त्रालय, व्यय विभाग (एस० व एल० प्रभाग)।
2. गृह मन्त्रालय।
3. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता।
4. मुख्य निदेशक, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली।
5. निदेशक, संगणक केन्द्र, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली।
6. सांख्यिकी विभाग एवं केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के समस्त अधिकारी।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

वि० स० दिव्याणी, सचिव

समाज कल्याण विभाग

संकल्प

नई दिल्ली-1, दिनांक 2 मार्च 1970

सं० एफ०-1-44/69-एस० डब्ल्यू०-3—समाज कल्याण के दिनांक 22 अप्रैल, 1969 के संकल्प संख्या-एफ०-1-16/69-एस०-डब्ल्यू०-3, जिसके द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (समवाय) का सामान्य निकाय गठित हुआ, का उद्देशिक संशोधित करते हुए भारत सरकार श्रीमती अन्नी बायल (सामाजिक कार्य-कर्ता) को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (समवाय) के सामान्य निकाय में सहर्ष सदस्य नियुक्त करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति निम्नांकित को भेजी जाए :—

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सब सदस्य ।
2. सब राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र ।
3. भारत सरकार के सब मन्त्रालय/विभाग ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय ।
5. मन्त्री-परिषद सचिवालय ।
6. योजना आयोग ।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय/प्रधान मन्त्री सचिवालय ।
8. प्रेस सूचना ब्यूरो ।
9. केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, नई दिल्ली ।
10. कम्पनी-कार्य विभाग ।
11. कम्पनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली ।
12. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड, कानपुर ।
13. सचिव, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली (50 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
14. राज्यों के समाज कल्याण मनाहकार बोर्डों के सब अध्यक्ष ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।

ज्वाला सिंह त्यागी, अवर सचिव

गृह मन्त्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 मार्च 1970

सं० 262/1/70-प्र० सं० प्र० (2)—इस समय संसद के समक्ष विचाराधीन लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक के अधिनियमित होने पर, लोकपाल और लोकायुक्त की नई संस्थाएं स्थापित हो जाएंगी । केन्द्रीय मतर्कता आयोग के वर्तमान गठन को इन नई संस्थाओं के रूप में परिवर्तित करने के कार्य को सुगम बनाने की दृष्टि से, केन्द्रीय मतर्कता आयोग का गठन करने वाले गृह मन्त्रालय के तारीख 11 फरवरी, 1964 के संकल्प संख्या 24/7/64-प्र० सं० प्र० को संशोधित करना आवश्यक हो गया है । तदनुसार, भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि उक्त संकल्प के पैरा 3 (ग) का निम्नलिखित संशोधित रूप तत्काल लागू होगा :—

निम्नलिखित पैरा की अगह

“(ग) वह छः वर्ष की अवधि के लिए या अपने 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद पर नियुक्त रहेंगे,

निम्नलिखित पैरा प्रस्थापित किया जाए

“(ग) छः वर्ष की अवधि के लिए पद पर नियुक्त रहेंगे ।”

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों, आदि को भेजी जाए और यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

ज० म० लालबानी, संयुक्त सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय**(खाद्य विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 1970

संकल्प

सं० 2-1/70-एस० पी० वाई०—भारत सरकार ने अपने संकल्प सं० 20(1)-टैरि०/68, तारीख 7 फरवरी 1968 में टैरिफ आयोग से चीनी की लागत संरचना और चीनी उद्योग को देय उचित कीमत के विषय में एक जांच करने की प्रार्थना की थी । आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है । चीनी के कारखानों के जोन बनाने और चीनी के कारखाने के द्वारा कीमत निकालने के लिए उसके द्वारा तैयार की गई लागत अनुसूचियों के संबंध में आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने विचार कर लिया है ।

2. आयोग ने निम्नलिखित 15 लागत जोनों की सिफारिश की है, अर्थात् :—

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. पंजाब | 9. गुजरात |
| 2. हरियाणा | 10. मध्य प्रदेश |
| 3. राजस्थान | 11. महाराष्ट्र |
| 4. पश्चिमी उत्तर प्रदेश | 12. मैसूर |
| 5. मध्य उत्तर प्रदेश | 13. आंध्र प्रदेश |
| 6. पूर्वी उत्तर प्रदेश | 14. तमिल नाडु और पांडीचेरी |
| 7. उत्तरी बिहार | 15. उड़ीसा, आसाम, केरल और |
| 8. दक्षिणी बिहार | बंगाल । |

3. जोनों के बनाए जाने के संबंध में विभिन्न विचारों पर ध्यान देने के पश्चात् आयोग ने कहा है कि कुल मिला कर अनुसरण किया जाने वाला व्यावहारिक रास्ता कीमत जोनों की संख्या को पर्याप्त रूप से बढ़ाना होगा ताकि अन्य बातों के साथ-साथ लागत संरचना की विषमताएं, यदि पूरी तौर से दूर नहीं की जा सकें, तो भी, कम तो हो जाएं । टैरिफ आयोग ने अपेक्षाकृत छोटे और समरूप जोनों की और अधिक संख्या के पक्ष में सबल कारण बताए हैं, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि बड़े आकार के जोनों में इन बड़े जोनों में व्यापक अन्तर मौजूद होने के कारण काफी विषमताएं उत्पन्न कर दी हैं । भारत सरकार ने टैरिफ आयोग की इस सम्बन्ध में सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ।

4. सरकार ने तीन वर्षों में अर्थात् 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के लिए चीनी के उद्ग्रहण कीमत नियत करने के लिए टैरिफ आयोग द्वारा तैयार की गई लागत अनुसूचियों को अपनाने का विनिश्चय भी किया है, जैसी कि आयोग ने सिफारिश की है ।

5. जहाँ तक प्रत्यागम का सम्बन्ध है, टैरिफ आयोग ने सिफारिश की है कि उसके विचार में इस उद्योग विशेष की मौजूदा जरूरतें चीनी की एक उचित कीमत निकालने में रुढ़िगत तरीके को छोड़ कर और उसकी बजाए प्रति क्विंटल एक एकल रूप रकम को अन्य लागतों में जोड़े जाने के लिए एक मार्जिन के रूप में अपना कर अधिक सामयिक रूप से पूरी हो सकेगी। तदनुसार आयोग इस परिणाम पर पहुँचा है कि इस प्रकार जोड़े जाने के लिए 10.50 रु० प्रति क्विंटल एक उचित रकम होगी। भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया। इस रकम का आशय पूंजी पर ब्याज, लाभ, कराधान आदि को सम्मिलित करना है।

6. टैरिफ आयोग ने पुनर्वासि भत्ते के अनुदान और क्षमता के अनुसार एक श्रेणीबद्ध स्लैब पद्धति से उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशों की हैं। सम्बद्ध हितों के साथ परामर्श होने तक इन सिफारिशों पर विनिश्चय अस्थगित कर दिया गया है।

7. टैरिफ आयोग ने गन्ने, चीनी, गुड़, खाण्डसारी आदि के उत्पादन सम्बन्धी अन्य कई विषयों पर भी सिफारिशों की हैं। राज्य सरकारों और सम्बद्ध हितों के साथ परामर्श करने के पश्चात् इन विषयों पर विचार करने की प्रस्थापना है। ऐसे विचार किए जाने के पश्चात् इन विषयों पर विनिश्चय किए जाएंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को संसूचित की जाए और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० पी० मथरानी, सचिव

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 1970

सं० एफ० 14-61/69-यू-1—पुनर्वासि मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या आर० एच० ई०-11(5)52, दिनांक 5 सितम्बर 1952 की दूसरी अनुसूची के पैराग्राफ 6(ई) में विविष्ट उपबंधों का अनुसरण करते हुए और उसी मंत्रालय की अधिसूचना संख्या आर० एच० ए० ई०-5(12)/53, दिनांक 21 मई 1955 के पैराग्राफ 3 को साथ पढ़ते हुए भारत सरकार कर्नल बी० एच० जैदी, सदस्य, राज्य सभा को 7 दिसम्बर 1969 से तीन वर्ष की अवधि के लिए वेशबन्धु कालेज, कालकाजी, नई दिल्ली के प्रशासन बोर्ड के सदस्य के रूप में सहर्ष नामित करती है।

राम स्वरूप चिटकारा, उप शिक्षा सलाहकार

पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 1970

संकल्प

सं० एफ० 19-टी०(14)/68—केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के यातायात और परिवहन प्रभाग के अध्यक्ष, डा० एन० एस० श्रीनिवासन, इस मंत्रालय के संकल्प सं० 19-टी०

(14)/68, दिनांक 3 जून 1969 अधीन गठित सड़क सुरक्षा के अध्ययन दल के सदस्य के तौर पर नियुक्त किए गए हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेज दी जाए और भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

के० सी० जोशी, उप-सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च 1970

संकल्प

सं० 6-पी० जी०(1)/70—भारत सरकार को कोचीन पत्तन का वर्ष 1968-69 का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। प्रतिवेदन के मुख्य-मुख्य तथ्य नीचे दिए जा रहे हैं :—

1. वित्तीय परिणाम :

(क) पत्तन निधि : आलोच्य वर्ष में राजस्व आय (कनहारी और विशेष आय को छोड़ कर) 372.09 लाख रुपए हुई, जब कि 1967-68 में यह 377.37 लाख रुपए हुई थी। 1968-69 में आय में कमी मुख्यतः “जल गोदियों और घाट और पत्तन विभाग” के अंतर्गत हुई परन्तु “भूमि और भवन” के अंतर्गत काफी वृद्धि हुई।

आलोच्य वर्ष में राशि (कनहारी लेखा के व्यय और आरक्षित निधि और पूंजी लेखा को दिए गए अंशदानों को छोड़ कर) 280.66 रुपए हुई, उसके विपरीत 1967-68 में यह राशि 242.37 रुपए थी।

इस वर्ष पूंजी लेखा को 67.66 लाख रुपए का अंशदान दिया गया, जब कि गत वर्ष इस अंशदान की राशि 25.19 लाख रुपए थी। विभिन्न आरक्षित निधियों को दिए गए अंशदान नीचे दिए जा रहे हैं :—

	(राशि लाख रुपयों में)	
	1967-68	1968-69
राजस्व आरक्षित निधि	1.00	2.00
दुर्घटना निधि	1.82	2.00
पुनर्निर्माण और प्रतिस्थापन निधि	19.80	25.00

(ख) कनहारी लेखा : इस वर्ष कुल आय और व्यय क्रमशः 16.49 लाख रुपए और 7.21 लाख रुपए हुआ।

(ग) आरक्षित निधियाँ : आलोच्य वर्ष के अंत में विभिन्न आरक्षित निधियों में अधिशेष की स्थिति संतोषजनक रही। इन निधियों का इतिशेष इस प्रकार रहा है :—

	(रुपए लाखों में)	
राजस्व आरक्षित निधि	.	65.63
दुर्घटना निधि	.	29.53
पुनर्निर्माण और प्रतिस्थापन निधि	.	143.44

(ब) ऋण : विचाराधीन वर्ष में कुल ऋण प्रभार 43.15 रुपए रहा, जब कि गत वर्ष में यह राशि 38.32 लाख रुपए थी। इस वित्तीय वर्ष के अंत में पत्तन का संपूर्ण पूंजीगत ऋण 497.77 लाख रुपए था। (1967-68 के अंत में यह राशि 448.05 लाख रुपए थी) इस ऋण राशि में से 410.05 लाख रुपए भारत सरकार के 52.12 लाख रुपए इलजीमीन बैंक, नीदरलैंड के और शेष केरल सरकार के हैं।

2. यातायात :

(क) व्यापार : इस वर्ष पत्तन ने 51.90 लाख टन यातायात की धराउठाई की इसकी तुलना में गत वर्ष 54.25 लाख टन की धराउठाई की गई थी। 37.83 लाख टन का आयात हुआ। इसके विपरीत गत वर्ष 37.32 लाख टन माल का आयात हुआ था। बैंकर को छोड़ कर निर्यात की मात्रा 14.07 लाख टन रही, इसके विपरीत गत वर्ष 16.93 लाख टन का निर्यात हुआ था। निर्यात में कमी होने का मुख्य कारण पी० ओ० एल० वस्तुओं के निर्यात में कमी का आना था।

(ख) पोत परिवहन : 1968-69 में पत्तन में प्रवेश करने वाले पोतों की संख्या, पालपोतों को छोड़ कर 1,083 थी और कुल एन० आर० टी० 49.49 लाख थी। इससे पिछले वर्ष की तदनु रूप संख्याएं 1,209 और 53.02 लाख एन० आर० टी० हैं। इस वर्ष 9,754 टन भार सहित 85 पालपोत इस पत्तन पर आए। 1967-68 में 11,023 टन भार सहित 96 पालपोत आए थे।

3. पूंजीगत व्यय :

इस वर्ष पूंजी खाते के अंतर्गत कुल 139.66 लाख रुपए व्यय हुए। यह राशि निम्नलिखित स्रोतों से पूरी की गई :—

1. सामान्य खाते से राजस्व अंशदान	67.66
2. कनहारी खाते से राजस्व अंशदान	2.00
3. भारत सरकार के ऋण से	70.00
	<hr/>
	139.66

कुछ महत्वपूर्ण कार्य निर्माणकार्य जो इस वर्ष पूरे किए गए अथवा अभी जारी हैं, नीचे दिए जा रहे हैं।

पूरे किए गए निर्माण-कार्य :

- 300×70 माल के गोदाम का निर्माण।
- टाइप 2 और 3 क्वार्टरों का निर्माण।
- टाइप 2, 3 और 4 क्वार्टरों को बहिर्जल प्रदाय से संबद्ध निर्माण-कार्य।
- विलिंगडन द्वीप के उत्तरी कोने पर अस्पताल का निर्माण।
- उत्तरी तथा दक्षिणी घाटों के बीच के शेष स्थान को गस्ता रोकना तथा बाढ़ को एलुमिनियम रंग से रंगना।

निर्माण कार्य जो जारी हैं :

- एर्नाकुलम घाट के दक्षिण में खुले घाट का निर्माण।
- 400'×90' के गोदाम का निर्माण।

3. इर्नाकुलम के नए तेलपोत घाट पर अग्निशमन।

4. भारिक-गृह निर्माण।

5. 12 फार्क लिफ्ट ट्रक लेना।

6. 4 घाट क्रेनों की पूर्ति।

4. श्रम और कल्याण उपाय :

श्रमिक संपर्क संतोषजनक बना रहा। विभिन्न कल्याण उपायों पर ध्यान दिया जाना बना रहा।

5. विचाराधीन वर्ष में कोचीन पत्तन न्यास द्वारा किए गए कार्य के लिए सरकार ने संतोष प्रकट किया।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि समस्त संबद्धों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० नारायणन, संयुक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 28 फरवरी 1970

सं० 24/3/68-एफ० पी०—समय-समय पर संशोधित, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प संख्या 1/29/58-एफ० पी०, तारीख 5 फरवरी 1959 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने एतद्वारा, श्री एम० वी० देसाई, कार्यकारी अध्यक्ष, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, बम्बई को उनके अपने कार्य के अतिरिक्त, इस अधिसूचना की तिथि से अगले आदेश तक, श्री आर० पी० नायक के स्थान पर फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

के० के० खान, अवर सचिव

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 1970

सं० डब्ल्यू० ई० 48/38/69—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 3 (बी) और 4 (iii) तथा (i) के अनुसार, भारत सरकार एतद्वारा डा० एस० एन० सराफ, निदेशक, योजना और समन्वय, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से डा० पी० डी० शुक्ला के स्थान पर केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड में शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती है।

2. तदनुसार 20 दिसम्बर 1958/29 अग्रहायण 1880 के भारतीय राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ई० एण्ड पी०-1(24)/

58, दिनांक 12 दिसम्बर 1958 (समय-समय पर संशोधित) में निर्दिष्ट प्रविष्टि—

“2. डा० पी० डी० शुक्ला,
संयुक्त शिक्षा सलाहकार,
शिक्षा मंत्रालय,
नई दिल्ली”

के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए :—

2. डा० एस० एन० सराफ,
निदेशक, योजना और समन्वय,
शिक्षा मंत्रालय,
नई दिल्ली।”

सं० डब्ल्यू० ई० 48/39/69—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 8 के अनुसार भारत सरकार, एतद्वारा डा० एस० एन० सराफ, निदेशक, योजना और समन्वय, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली, को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से डा० पी० डी० शुक्ला के स्थान पर केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के 'बोर्ड आफ गवर्नर्स' का सदस्य नामित करती है।

हंस राज छाबड़ा, अवसर सचिव

CABINET SECRETARIAT (Department of Statistics)

RESOLUTION

New Delhi-1, the 5th March 1970

No. DS/STS/4-69.—The National Sample Survey work is at present undertaken by the Department of Statistics. While the field work in all areas except West Bengal and Bombay City is carried out by the Directorate of National Sample Survey, which is a Government organisation, all other items of work such as designing of surveys, processing of data, preparation of reports and also field work in respect of West Bengal and Bombay City are entrusted to the Indian Statistical Institute on an agency basis. The expenditure incurred on this work by the Indian Statistical Institute is fully reimbursed by the Government by way of grants.

2. This dual control in the National Sample Survey work has brought in its wake many drawbacks, the most significant of which is the inordinate delay between collection of data and publication of results. Government have therefore been examining for some time the lines on which the National Sample Survey work should be reorganised. The Indian Statistical Institute Review Committee set up by the Government in 1969 recommended the entrustment of all aspects of National Sample Survey work (with the exception of the work relating to West Bengal and Bombay City) to one single organisation. This issue has also been examined by other informal Working Groups set up subsequently.

3. Recently, a three-man Committee consisting of Shri B. Sivaraman, Cabinet Secretary, Prof. V. M. Dandekar and Prof. Raghubar Bahadur, was requested to advise the Government on the lines on which such reorganisation should be given effect to. This Committee has among other things recommended the entrustment of all aspects of National Sample Survey work to a single government organisation located in the Cabinet Secretariat and governed by a Governing Council. It has further recommended that the Governing Council should be given sufficient independence and autonomy of decision so as to ensure that the collection, processing and publication of the N.S.S. data is free from undue influence.

4. Government have accepted the recommendations of the three-man Committee and have decided to set up an organisation called the "National Sample Survey Organisation" in the Department of Statistics, Cabinet Secretariat. The Directorate of N.S.S. will become a part of this organisation. All employees of Indian Statistical Institute engaged on National Sample Survey work, and such employees engaged on common services who become surplus to the needs of the Institute, would also be absorbed in this organisation. The absorption of these employees of the Institute would be arranged on such terms as to ensure that there is no deterioration in the conditions of their service.

5. All items of National Sample Survey, subject to such changes as the Government may direct from time to time, will be entrusted to this Organisation. The activities of this Organisation will be governed by a Governing Council composed as follows :—

Non-officials.

1. Chairman.
2. Two Statisticians from the Indian Statistical Institute.

3. Two Economists from Universities, Research Institutes, and other private organisations.

Officials.

4. Director, Central Statistical Organisation.
5. Two Directors of State Statistical Bureaux (in rotation).
6. Two Statistical/Economic Advisors of Central Government Ministries/Departments (in rotation).

N.S.S. Organisation Staff

7. Directors of functional divisions of the N.S.S. Organisation, including Survey, Design & Research, Economic Analysis, Field Operations, and Data Processing.
8. Chief Executive Officer, National Sample Survey Organisation—Member-Secretary.

6. The chairman shall be appointed for a period of five years. The term of appointment of other non-officials shall be two years each; the Directors of the State Statistical Bureaux and the Statistical/Economic Advisors of Central Government Ministries/Departments who are members of the above Council will also have a two-year term.

7. The Governing Council will have the requisite independence and autonomy of decision to ensure that the collection, processing and the publication of N.S.S. data is free from undue influence. It will have full authority to formulate its short period and long-term programmes and to approve the budget of the Organisation within the funds that may be provided by Government every year. This will include the choice of subjects or items on which data has to be collected in a given field of investigation or in a given period; the frequency with which the data on any item is to be collected; the deployment of relative resources in investigation and processing of different items; the preparatory or pilot work to be undertaken on different subjects; the sample design to be adopted, the tabulation to be prepared; the form in which the data are to be collected and processed, and the analysis and publication of results.

8. The Governing Council should not, however, encroach upon the legitimate spheres of activities of other statistical agencies of the Central and State Governments, though it may take action in suitable cases to fill up gaps in the information needed by Government for policy formulation and for improvement of existing data collected by other agencies by supplementary collection of data by the N.S.S. Organisation. In such cases the initiative should preferably come from the concerned Ministries or agencies, and where a proposal is initiated by the N.S.S. Organisation, it should have the concurrence and support of the concerned Ministries or agencies. Requests for collection or tabulation of data on behalf of other Ministries and agencies should not be accepted by the Council without the prior approval of Government. Having regard to the limitations of resources, the emphasis should be on developing a stable and organically connected programme of data collection designed to fill gaps in statistics necessary for policy formulation and its implementation rather than setting up an agency to meet *ad hoc* requests for data coming from several quarters.

9. The Governing Council should while drawing up the programme of survey to be undertaken during a period also

indicate the form in which and the dates by which the results will be published. The aim should be to publish the results in the forms of tables with notes within twelve months of the completion of that survey. Apart from the publication of tables and notes, the comprehensive economic analysis of the collection of data and its publication should also be treated by the Council as an integral part of its functions.

10. The Governing Council will have the power to approve the budget of the N.S.S. Organisation within the total funds that may be provided by Government every year. The Chief Executive Officer of the N.S.S. Organisation who will also be an *ex-officio* Secretary/Additional Secretary/Joint Secretary in the Department of Statistics, Cabinet Secretariat, will function within the framework of the budget approved by the Council and the programme of work determined by it, and he will be responsible for exercising all financial and administrative powers that may be vested in him for the working of the National Sample Survey Organisation. The Chief Executive Officer will issue formal orders to give effect to the decisions of the Council.

11. The expenditure relating to the N.S.S. Organisation and its Governing Council will be debitable to Major Head—39 and accounted for under Demand No. 48—Department of Statistics.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :

- (1) Ministry of Finance, Department of Expenditure (S&L Division).
- (2) Ministry of Home Affairs.
- (3) Indian Statistical Institute, Calcutta.
- (4) Chief Director, National Sample Survey, Ramakrishnapuram, New Delhi.
- (5) Director, Computer Centre, Ramakrishnapuram, New Delhi.
- (6) All officers in the Department of Statistics/CSO.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. L. GIDWANI, Secy.

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

RESOLUTION

New Delhi-1, the 2nd March 1970

No. F. 1-14/69/S.W. 3.—In partial modification of the Department of Social Welfare's Resolution No. F. 1-16/69-S.W.3, dated the 22nd April 1969, constituting the General Body of the Central Social Welfare Board (Company), the Government of India are pleased to nominate Smt. Annie Thayil, (Social Worker) as a member of the General Body of the Central Social Welfare Board (Company).

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :—

1. All the members of the CSWB.
2. All State Governments/Union Territories.
3. All Ministries/Departments of Government of India.
4. President's Secretariat.
5. Cabinet Secretariat.
6. Planning Commission.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Sectt./P.M.'s Sectt.
8. Press Information Bureau.
9. Accountant General, Central Revenue, New Delhi.
10. Department of Company Affairs.
11. Registrar of Companies, New Delhi.
12. Regional Director, Company Law Board, Kanpur.
13. Secretary, CSWB, New Delhi (with 50 spare copies).
14. All Chairmen, State Social Welfare Advisory Boards.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

J. S. TYAGIAS, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 12th March 1970

RESOLUTION

No. 262/1/70-AVD.II.—On the enactment of the Lokpal and Lokayuktas Bill, which is presently before the Parliament, the new institutions of Lokpal and Lokayuktas will be established. In order to facilitate the change-over from the present set-up of the Central Vigilance Commission to the new institutions, it has become necessary to amend the Resolution No. 24/7/64-AVD, dated the 11th February, 1964, issued by the Ministry of Home Affairs constituting the Central Vigilance Commission. Accordingly, the Government of India have decided that para. 3(c) of the said Resolution shall stand amended with immediate effect as indicated below :—

For "(c) will hold office) for a term of six years or till he attains the age of 65 whichever is earlier;"

Substitute "(c) will hold office for a term of six years;"

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, all Ministries of the Government of India, etc. and also that the Resolution be published in the Gazette of India.

J. M. LALVANI, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & YOUTH SERVICES

New Delhi, the 26th February 1970

No. F. 14-61/69-V.I.—In pursuance of the provision contained in paragraph 6(c) of the Second Schedule to the Government of India, Ministry of Rehabilitation, Notification No. RHE-11(5)/52 dated the 5th September, 1952 read with paragraph 3 of that Ministry's Notification No. RHAE-5(12)/53 dated the 21st May, 1955, the Government of India are pleased to re-nominate Colonel B. H. Zaidi, Member, Rajya Sabha to be a member of the Board of Administration of the Desh-bandhu College, Kalkaji, New Delhi, for a term of three years with effect from the 7th December, 1969.

R. S. CHITKARA, Dy. Educational Adviser

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

Transport Wing

RESOLUTION

New Delhi, the 4th March 1970

No. 19-T(14)/68.—Dr. N. S. Srinivasan, Head of the Traffic and Transport Division of the Central Road Research Institute, New Delhi, has been appointed as a member of the Study Group on Road Safety constituted under this Ministry's Resolution No. 19-T(14)/68 dated the 3rd June, 1969.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

K. C. JOSHI, Dy. Secy.

RESOLUTION

New Delhi, the 7th March 1970

No. 6-PG(1)/70.—The Government of India have received the Administration Report of the Port of Cochin for the year 1968-69. The salient features of the Report are given below :—

1. FINANCIAL RESULTS :

(a) *Port Fund* : The revenue receipts (excluding Pilotage and special receipts) during the year amounted to Rs. 372.09 lakhs as compared to Rs. 377.37 lakh during 1967-68. The fall in income in the year 1968-69 was mainly under 'Wet Docks and Wharves' and 'Port Department', while there was substantial increase under 'Lands and Buildings'.

The expenditure (excluding that charged to the Pilotage Account and contributions to the Reserve Fund and Capital Account) during the year under review was Rs. 280.66 lakhs as against Rs. 242.37 lakhs in 1967-68.

During the year, a contribution of Rs. 67.66 lakhs was made to the Capital Account as against Rs. 25.19 lakhs in the previous year. The contributions made to various Reserve Funds are indicated below :—

	(Amount in lakhs of Rupees).	
	1967-68	1968-69.
Revenue Reserve Fund	1.00	2.00
Accident Fund	1.82	2.00
Renewals & Replacement Fund	19.80	25.00

(b) *Pilotage Account* : The gross income and expenditure during the year were Rs. 16.49 lakhs and Rs. 7.21 lakhs, respectively.

(c) *Reserve Funds* : The position with regard to the balances in the various reserve funds at the end of the year was satisfactory. The closing balance in the funds were as under :—

	(Rs. in lakhs)	
Revenue Reserve Fund	65.63
Accident Fund	29.53
Renewals & Replacement Fund	143.44

(d) *Debt* : The aggregate of debt charges incurred during the year under review amounted to Rs. 43.15 lakhs as against Rs. 38.36 lakhs in the preceding year. The total Capital debt of the Port at the close of the financial year stood at Rs. 497.77 lakhs (as against Rs. 448.05 lakhs at the end of 1967-68), out of which a sum of Rs. 410.05 lakhs was due to the Government of India, Rs. 52.12 lakhs to the Algemeene Bank, Netherlands, and the balance to the Government of Kerala.

2. TRAFFIC :

(a) *Trade* : The total traffic handled by the Port during the year was 51.90 lakh tonnes as against 54.25 lakh tonnes last year. Imports accounted for 37.83 lakh tonnes as against 37.32 lakh tonnes in the previous year. Exports, excluding bunkers, amounted to 14.07 lakh tonnes as against 16.93 lakh tonnes in the previous year. The fall in exports during the year was mainly due to reduction in the exports of P.O.L. products.

(b) *Shipping* : The number of vessels, excluding sailing vessels, which entered the port during 1968-69 was 1083 with a total NRT of 49.49 lakhs. The corresponding figures for the previous year were 1209 and 53.02 lakh NRT. 85 sailing vessels with a tonnage of about 9,754 visited the port during the year as against 96 with a tonnage of 11,023 during 1967-68.

3. CAPITAL EXPENDITURE :

The total expenditure on Capital Account during the year was Rs. 139.66 lakhs. This expenditure was met from the following sources :—

(i) Revenue contribution from General Account	..	67.66
(ii) Revenue contribution from Pilotage Account	..	2.00
(iii) Loan from Government of India	70.00
Total	..	139.66

Some of the important works completed during the year or in progress are mentioned below :—

WORKS COMPLETED :

1. Construction of a ware house of size 300' × 70'.
2. Construction of types II & III quarters.
3. Works connected with external water supply to type II, III and IV quarters.

4. Construction of a hostel at the North and of Wellingdon Island.

5. Barricading the gap between North and South Tanker Berths and painting pale fencing with aluminium paint.

WORKS IN PROGRESS :

1. Construction of an Open Berth South of Ernakulam Wharf.
2. Construction of ware-house 400' × 90'.
3. Fire fighting at the new oil tanker berth at Ernakulam.
4. Construction of Portage houses.
5. Procurement of 12 Fork Lift Trucks.
6. Supply of 4 Wharf Cranes.

4. LABOUR AND WELFARE MEASURES :

Labour relations continued to be satisfactory. Different welfare measures continued to receive attention.

5. Government view with satisfaction the work done by the Cochin Port Trust Board during the year under review.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. NARAYANAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING AND COMMUNICATION

New Delhi, the 7th October, 1969

No. 4/9/68-Coord/GSR.—In exercise of the powers conferred by Section 20A(i) of the Press & Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956, namely :—

1. (a) These rules may be called the Registration of Newspapers (Central) Amendment Rules, 1969.
- (b) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
2. In the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956 for rule 11 the following rule shall be substituted, namely :—

"11. Annual Report—The Press Registrar shall submit to the Central Government on or before the 30th September of each year, an annual report containing information and statistics about the Press in India, and, in particular, circulation trends in different categories of newspapers and the trends in the direction of common ownership of more than one newspaper."

S. PADMANABHAN, Under Secy.

New Delhi-1, the 28th February 1970

No. 24/3/68-FP.—In pursuance of the Resolution of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 1/29/58-FP dated the 5th February, 1959, as amended from time to time, the Central Government hereby nominates Shri M. V. Desai, acting Chairman, Central Board of Film Censors, as the Chairman of the Film Advisory Board, Bombay, in addition to his own duties, with immediate effect vice Shri R. P. Nalk, till further orders.

K. K. KHAN, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour & Employment)

New Delhi, the 12th March 1970

No. WE-48/39/69.—In pursuance of rule 3(b) read with 4(iii) & (vi) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers' Education, the Government of India, hereby appoints Dr. S. N. Saraf, Director, Planning & Coordi-

nation, Ministry of Education, New Delhi as representative of the Ministry of Education on the Central Board for Workers' Education *vice* Dr. P. D. Shukla, with effect from the date of this notification.

2. The following changes shall be made accordingly in the Ministry of Labour & Employment Notification No. E&P4(24)/58, dated the 12th December, 1958, published in the Gazette of India Part I, Section 1, dated December 20, 1958/Agrahayana 29, 1880, as amended from time to time.

For the existing entry :—

- "1. Dr. P. D. Shukla,
Joint Educational Adviser,
Ministry of Education,
New Delhi.

The following entry shall be substituted :—

- "2. Dr. S. N. Saraf,
Director,
Planning and Coordination,
Ministry of Education,
New Delhi.

New Delhi, the 12th March 1970

No. WE-48/39/69.—In pursuance of Rule 8 of the Rules and Regulation of the Central Board for Workers' Education, the Government of India hereby nominates Dr. S. N. Saraf, Director, Planning and Coordination Ministry of Education and Youth Services, New Delhi as a member of the Board of Governors of the Central Board for Workers' Education *vice* Dr. P. D. Shukla with effect from the date of this notification.

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.

